सोने का आयात

838. **श्री राम सेवक हजारी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सोने की नीलामी जारी रखने के लिये सोने का आयात करने का है ;

(ख) यदि हां, तो इसके उद्देश्य क्या हैं; और

(ग) इस बारे में क्या निर्णय किया गया है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क), (ख) तथा (ग). फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है । भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है, जो स्वर्ण नीति के सभी पहलुओं पर विचार करेगी और समुचित सिफारिशें पेश करेगी । यह सुझाव समिति को भेज दिया जायेगा ।

आर्थिक विकास के लिए विश्व बैंक सहायता

839. **श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्व बैंक ने हाल में भारत को उसके आर्थिक विकास के लिये कितनी धनराशि दी है ;

(ख) इसमें से उत्तर प्रदेश में औद्योगिक और कृषि विकास के लिये कितनी धनराशि मंजूर की गई है ;

(ग) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने इस राशि में से अतिरिक्त धनराशि की मांग की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी पूरा ब्योरा क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) वर्ष 1977–78 के दौरान विश्व बैंक के साथ कुल 875.31 करोड़ रुपए के ऋण करारों पर हस्ताक्षर किए गए थे । चालू वित्त वर्ष में विश्व बैंक समूह से मिलने वाली सहायता के 1033.75 करोड़ रुपए तक बढ़ जाने की सम्भावना है ।

(ख) विदेशों से मिलने वाले सभी साधन जिसमें विश्व बैंक से मिलने वाली राशि भी शामिल है, साधनों के केन्द्रीय पूल के अन्तर्गत आ जाते हैं । राज्यों के क्षेत्र में विश्व बैंक की सहायता से चलने वाली परियोजनाएं अनिवार्य रूप से राज्य की वार्षिक योजना का अंग होती हैं । इसके अलावा कुछ और परियोजनाएं भी केन्द्रीय क्षेत्र में शुरू की जाती हैं । ऐसी परियोजनाओं से होने वाला लाभ किसी विशेष राज्य तक सीमित नहीं होता । इस श्रेणी में ग्रामीण विद्युतीकरण और सिंगरौली सुपर तापीय बिजली घर जैसी परियोजनाएं शामिल हैं जिनका उत्तर प्रदेश के औद्योगिक और कृषि विकास में बहुत बड़ा योगदान होगा । विश्व बैंक की सहायता से भारतीय औद्योगिक ऋण तथा निवेश निगम, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक तथा कृषि पुनर्वित्त तथा विकास निगम जैसे अभिकरणों के माध्यम से उपलब्ध ऋणों से कई राज्यों को लाभ पहुंचेगा ।

साठ करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाली उत्तर प्रदेश जलपूर्ति और मल-निकासी परियोजना के लिए विश्व बैंक समूह से मिलने वाली सहायता में से धन दिया जा रहा है । राष्ट्रीय बीज परियोजना के लिए भी, जो देश में 5 राज्यों में चलाई जा रही हैं, बैंक से सहायता प्राप्त हो रही है और इससे जिन 5 राज्यों को लाभ पहुंचेगा उनमें उत्तर प्रदेश एक है । इसी प्रकार राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परियोजना भी बैंक की सहायता से शुरू की गई है और इस परियोजना से लाभ पाने वाले राज्यों में से एक राज्य उत्तर प्रदेश होगा ।